

साउथ इण्डिया से मांग उठी, अब संसद की कुछ बैठक दक्षिण भारत में भी हों

वाय.एस.आर. कांग्रेस के तिरुपति से सांसद ने संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजीजू को पत्र लिख कर यह मांग की

लक्ष्मण वेंकट कुची-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। अब दक्षिण भारत से मांग उठ रही है कि दक्षिण भारत में संसद की मीटिंग करवाई जाए जैसे कर्नाटक विधानसभा की बैठक बेलागावी में भी होती है। दक्षिण भारत से संसदीय बैठकों का विकेन्द्रिकरण करने की बात की जा रही है।

इस तरह के विचार का समर्थन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भी किया था।

वाय.एस.आर.सी.पी. के तिरुपति के सांसद एम. गुरुमूर्ति ने संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू को इस बारे में पत्र लिखा है, जिसका समर्थन तमिलनाडु के सांसद कार्ति चिदम्बरम व अन्य सांसदों ने भी किया।

तिरुपति सांसद ने इस मांग के पीछे तर्क और इतिहासिक परिप्रेक्ष्य पेश किया और कहा कि ऐसा करने से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा और दिल्ली के खराब मौसम से सांसदों को

तमिलनाडु से निर्वाचित सांसद कार्ति चिदम्बरम सहित कई दक्षिण भारत के सांसदों ने इस मांग का समर्थन किया।

इन सांसदों के अनुसार, अम्बेडकर व वाजपेयी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। वाजपेयी का कहना था, यह प्रशासनिक कदम देश में एकता का भाव और मजबूत करेगा, तथा संसद को जनता के नजदीक लायेगा।

इस मांग के समर्थक सांसदों का यह भी कहना था, इस कदम से सभी सांसदों को दिल्ली की भीषण सर्दियों के मौसम से राहत मिलेगी और कार्यकुशलता बढ़ेगी।

इतिहासिक दृष्टि से यह सच है कि, 1988 में भी ऐसा एक प्रस्ताव प्राइवेट मैम्बर बिल के मार्फत लोकसभा में उठाया गया था, पर अन्य प्राइवेट मैम्बर बिल की भांति, यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया था। पर, अब शायद इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेने का समय आ गया है, तथा इससे यह मैसेज जायेगा कि संसद वाकई में पूरे देश की राष्ट्रीय संस्था है।

आवागमन से राहत मिलेगी और काम बेहतर ढंग से हो सकेगा। इतिहासिक

उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि अम्बेडकर और वाजपेयी जी ने संसद के सत्रों के विकेन्द्रिकरण की बात की थी जिसमें एकता व सबको साथ लेकर चलने की भावना को बल मिलेगा तथा संसद सभी क्षेत्र के लोगों के करीब लाया जा सकेगा।

अपने पत्र में केन्द्रीय मंत्री एम. गुरुमूर्ति ने हर साल संसद की दो बैठकें दक्षिण भारत में करवाने का सुझाव दिया और उम्मीद जताई कि सरकार इस सार्थक सुझाव पर सकारात्मक तरीके से विचार करेगी।

इसी तरह का विचार 1968 में एक सदस्य ने निजी बिल के मार्फत पेश किया था पर विधेयक पारित नहीं हो सका, पर अब समय आ गया है कि ऐसा कदम उठाया जाए अगर संसद की बैठकों का विकेन्द्रिकरण कर दिया जाए तो जनता को लगेगा कि संसद उनके ज्यादा करीब आ गई है।

इससे यह साबित करने में भी मदद मिलेगी कि संसद राष्ट्रीय निकाय है और सिर्फ नई दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है।

‘पूर्व सी.जे.आई. ने पूजा स्थल सम्बंधी विवादों को जन्म दिया’

नई दिल्ली, 02 दिसंबर कांग्रेस ने सोमवार को उपासना स्थल अधिनियम- 1991 को पूरी तरह से लागू करने की मांग उठाई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अफसोस की बात है कि 20 मई 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने कुछ मौखिक ‘ऑब्जर्वेशन्स’ दी थी, जिसने मंदिर-मस्जिद वाली याचिकाओं का रास्ता साफ किया है। भाजपा उसका भरपूर राजनीतिक फायदा उठा रही है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा 20 मई 2022 को पूर्व सी.जे.आई. चंद्रचूड़ ने जो मौखिक टिप्पणी की थी उसके बाद से ही मस्जिदों व दरगाहों पर दावेदारी जताने की याचिकाओं की बाढ़ आ गई है।

हर जगह साम्प्रदायिक तनाव फैलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मगर 1991 में बने कानून को लागू करना अनिवार्य है। जयराम रमेश ने कहा कि हाल ही में सामने आए विभिन्न विवाद जैसे कि संभल में एक मस्जिद और अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दावा करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अडानी की मुश्किलें संसद तक ही सीमित नहीं

बांग्लादेश ने भी अडानी पावर कम्पनी से अपनी बिजली की खरीद आधी की

श्रीनन्द झा -
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। जहाँ गौतम अडानी विवाद के कारण संसद में गतिरोध बना हुआ है, वहीं, इस दिग्गज व्यवसायी को पड़ोसी बांग्लादेश में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने ‘अडानी पावर’ से की जाने वाली बिजली की मांग आधी कम कर दी है।

यह तनातनी पिछले महीने उस समय शुरू हुई, जब ‘अडानी पावर’ ने भुगतान में विलम्ब होने के कारण, बांग्लादेश को होने वाली सप्लाई घटाकर आधी कर दी थी।

बताया जाता है कि इसके बाद, बांग्लादेश ने अडानी से कह दिया कि वे अब केवल आधी सप्लाई ही करें।

अडानी ग्रुप, 25 साल के अनुबन्ध के तहत, बांग्लादेश को पावर-सप्लाई कर रहा है। यह अनुबन्ध 2017 में हुआ था, जब बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री थीं। पावर-सप्लाई ‘अडानी पावर’ द्वारा झारखंड में स्थापित की गई दो इकाइयों से की जा रही थी। इनमें से प्रत्येक की क्षमता करीब 800 मेगावाट थी। रिपोर्टों के अनुसार, यह प्लॉट नवम्बर में केवल 4.1 प्रतिशत क्षमता के साथ चला। पिछली सदियों तक,

अडानी पावर कम्पनी, अपने झारखण्ड स्थित पावर प्लांट की दो इकाइयों से, जिनकी पावर जनरेशन की क्षमता 16 सौ मेगावाट थी, से बांग्लादेश को नियमित बिजली सप्लाई कर रही थी, अब नवम्बर यह प्लांट 41 प्रतिशत क्षमता पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि, बांग्लादेश ने अडानी से बिजली खरीद आधी कर दी है।

झगड़ा शुरू हुआ गत माह से, जब अडानी की कम्पनी ने बांग्लादेश को दी जा रही सप्लाई को आधा कर दिया था, भुगतान देरी से मिलने का बहाना करके। जवाबी कार्यवाही में बांग्लादेश ने अडानी की कम्पनी को पत्र लिख कर कहा, ‘अब आप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई आगे के लिए आधी ही कर दें।’

अपुष्ट खबरों के अनुसार बांग्लादेश चाहता है कि अडानी अपनी बिजली सप्लाई की दर में भारी कमी करे, क्योंकि, भारत की अन्य पावर सप्लाई कम्पनियों लगभग औसतन 9.57 टका प्रति यूनिट की दर से बिजली सप्लाई कर रही हैं, जबकि, अडानी पावर कम्पनी 14.87 टन प्रति यूनिट की दर से बांग्लादेश को बिजली बेच रही है।

बांग्लादेश करीब 1000 मेगावाट बिजली प्रतिमाह खरीद रहा था। ‘अडानी पावर’ के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह फर्म बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करती आ रही है, हालाँकि बढ़ाता जा रहा उधार एक बड़ी चिन्ता का विषय है। इसके कारण प्लांट का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी सरकार ने संविधान पर चर्चा की विपक्ष की मांग मानी

संभावना है कि मंगलवार से संसद के दोनों सदनों में सुचारु रूप से काम होगा

जाल खंबाता -
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। संसद के दोनों सदनों का काम-काज मंगलवार से शुरू हो सकता है क्योंकि मोदी सरकार ने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर लिया है कि संविधान पर दो दिन की विशेष चर्चा हो।

राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रकार की चर्चा कराने के लिये सदन के सभापति को पत्र लिखा था। इसी प्रकार का एक पत्र 26 नवम्बर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखा था।

संविधान पर चर्चा लोकसभा में 13 तथा 14 दिसम्बर को तथा राज्य सभा में 16 एवं 17 दिसम्बर को होगी। सरकार, संसद के निरन्तर गतिरोध के समाधान की खातिर, संविधान पर बहस कराने की विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है। ज्ञातव्य है कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत, अर्थात्

लोकसभा में 13 और 14 दिसम्बर को तथा राज्यसभा में 16 व 17 दिसम्बर को संविधान पर चर्चा होगी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बारे में स्पीकर ओम बिड़ला को चिट्ठी लिखी थी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजा था।

शुरू में सरकार ने संविधान पर चर्चा कराने से इन्कार कर दिया था, इस वजह से 25 नवम्बर से शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद संसद में एक दिन भी काम नहीं हुआ।

25 नवम्बर से ही संसद टप पड़ी है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजजू ने कहा कि सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के कार्यालय में सदन के सभी नेताओं की मीटिंग हुई तथा यह तय हुआ कि मंगलवार से सदन की कार्यवाही निर्विघ्न रूप से शुरू हो जायेगी तथा उस दिन सदन में पहला विधेयक पेश एवं पारित हो जायेगा।

इस घटनाक्रम पर बयान देते हुये, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा ‘ऐसी आशा है कि मोदी सरकार दोनों सदनों में कल (मंगलवार) से काम होने देगी।’ शीतकालीन सत्र के आरम्भ से ही, दोनों सदनों में कोई काम-काज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि विपक्ष आसनों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सन् 2000 के मालपुरा दंगों में आठ को आजीवन कारावास

जयपुर, 2 दिसंबर। सांप्रदायिक दंगा मामलों की विशेष अदालत ने 24 साल पहले टोंक के मालपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगे के दौरान, हत्या करने वाले अभियुक्तों इस्लाम, मोहम्मद इशाक, अब्दुल रज्जाक, इरशाद, मोहम्मद जफर, साजिद अली, बिलाद अहमद और मोहम्मद हबीब को

अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने धारदार हथियारों से इस निर्ममता पूर्ण घटना को अंजाम दिया। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही, अदालत की पीठासीन अधिकारी श्वेता गुप्ता ने अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि अभियुक्तों ने धारदार हथियारों से निर्ममतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज होगी महाराष्ट्र के भाजपा विधायक दल की बैठक

पहले यह बैठक सोमवार 2 दिसम्बर को होने वाली थी

जाल खंबाता -
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। महाराष्ट्र में भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की मीटिंग, जो 2 दिसम्बर को होनी थी, 3 दिसम्बर तक के लिये टाल दी गई है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा गुजरात के पूर्व मुख्य मंत्री विजय रूपानी को महाराष्ट्र भाजपा के विधायक दल के नेता के चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है।

रूपानी ने कहा कि दोनों पर्यवेक्षक जाकर, प्रत्येक विधायक से मिलेंगे तथा सम्बन्धित जानकारी पार्टी हाईकमान को देंगे। इसके बाद, हाईकमान के निर्देशानुसार, पार्टी नेता की घोषणा कर दी जायेगी।

इस बीच, शिव सेना नेता संजय शिरसत ने कहा है कि उनके नेता तथा निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे महायुति सरकार के गठन में बाधा नहीं दें तथा पार्टी की भी कोई माँग नहीं है। शिंदे के नजदीकी साथी शिरसत

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को पर्यवेक्षक बनाया गया है, वे सभी विधायकों से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे।

शिवसेना और एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट ने साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे सरकार गठन में बाधा नहीं दें और उनकी पार्टी की कोई मांग नहीं है।

असल में शिंदे व उनकी पार्टी को लेकर भारी अटकलें लगाई जा रही हैं पर शिंदे ने अपने गांव से लौटने के बाद स्पष्ट कर दिया कि महायुति पूरी तरह से एक जुट है।

इधर शिंदे के पुत्र को लेकर भी कई अटकलें चल रही हैं, जिनका उन्होंने खंडन किया और कहा कि वे किसी भी पद की दौड़ में नहीं हैं।

ने कहा, ‘सब कुछ इतनी स्पष्टता के साथ कह देने के बाद, मेरे खयाल से उन (शिंदे) पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। वरिष्ठ नेता जो कुछ भी कहेंगे, वह हमें स्वीकार होगा। महायुति में कोई मतभेद नहीं है। मेरे खयाल से, नेताओं एकनाथ शिंदे, देवेन्द्र फड़नवीस तथा

अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा, ‘मुझे सत्ता में पद पाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ कि मैं राज्य मंत्रिमण्डल के किसी पद की दौड़ में नहीं हूँ।’

अस्वस्थ होने के कारण, थोड़े से समय के लिये अपने गृहनगर में ठहरने के बाद, एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति के सभी मित्र एक-दूसरे के साथ हैं तथा नये मुख्यमंत्री की घोषणा जल्दी ही हो जायेगी।

उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार का पिछले ढाई साल का काम इतिहास में याद किया जायेगा। यही कारण है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया तथा विपक्ष को नकार दिया, यहाँ तक कि उसे विपक्ष का नेता चुनने का अवसर भी नहीं दिया। महायुति के तीनों दलों के बीच अच्छी समझ-बूझ है।’

लेकिन उनकी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को एक बार पुनः यह माँग की कि शिंदे के नेतृत्व में राज्य में हुये विकास-कार्यों के आधार पर, उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकारी कर्मचारी को एक पद पर रहने का अधिकार नहीं

जयपुर, 2 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होता है। सक्षम अधिकारी नियमों की बिना अवहेलना किए उसका दूसरी जगह तबादला कर सकता है। इसके अलावा, अदालत को प्रशासनिक

हाईकोर्ट ने कहा, जब तक नियमों की अवहेलना नहीं हो अदालत को तबादला आदेशों में देखल नहीं देना चाहिए।

और जनहित में किए गए तबादला आदेश पर दखल नहीं देना चाहिए, जब तक कि उसमें नियमों की अवहेलना नहीं हुई हो। अदालत ने कहा कि यदि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पहली बार बांग्लादेश के कूटनीतिक संस्थानों पर तोड़फोड़ हुई

शेख हसीना के पलायन के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जारी हिंसा पर अब भारत में उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया होने लगी है

अंजन राय-
राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। बांग्लादेश में हिंदुओं के संस्थापनों पर लगातार हो रहे हमलों के निशान भारत के पूर्वी भाग व पूर्वोत्तर भाग की राजनीति पर भी दिखने लगे हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के बांग्लादेश काउन्सिलर ऑफिस पर हमला होना तथा पश्चिम बंगाल के कुछ राजनैतिक घटनाक्रम बांग्लादेश की हिंसा का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। यह एक संकेत है कि भारत और बांग्लादेश के सम्बंधों में भारी बदलाव आ गया है और अगरतला में बांग्लादेश के कार्यालयों पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। अगरतला में एक बड़ी भीड़ ने बांग्लादेशी कान्सुलेट पर हमला कर दिया। विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस विरोध प्रदर्शन की निंदा की और जब से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने

- पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेशी काउन्सिलर ऑफिस पर गुस्ताई भीड़ ने हमला किया और भारी तोड़-फोड़ की।
- अगरतला की एक बस पर बांग्लादेश में हुए हमले की खबर ने लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी।
- जहां जनता की उत्तेजना बढ़ रही है, वहीं प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया बेहद अटपटी है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, स्पष्ट है ममता बनर्जी ने बयान अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए दिया था।
- इसके विपरीत प. बंगाल की एक इस्लामिक पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
- बांग्लादेश में जब तक अवामी लीग का राज था तब तक कट्टरपंथियों पर अंकुश था पर अब कट्टरपंथी मनमानी कर रहे हैं और अंतरिम सरकार कुछ नहीं कर रही है।

देश छोड़ा है, वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है, इस पर भारत में भारी गुस्सा है तथा उसी की वजह से यह अगरतला वाली घटना हुई है।

बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ साम्प्रदायिक भारत में इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देखी गई, खासकर पश्चिम बंगाल में। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी अंतरिम

हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी कर्मचारी को एक ही जगह पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होता है। सक्षम अधिकारी नियमों की बिना अवहेलना किए उसका दूसरी जगह तबादला कर सकता है। इसके अलावा, अदालत को प्रशासनिक

अनूप बरतरिया का गिरफ्तारी वारन्ट जमानती में बदलने से इंकार

जयपुर, 2 दिसंबर। चेक अनादरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-8 महानगर प्रथम ने लोन के पेटे जमा कराए गए करीब 2.59 करोड़ रुपए राशि के चेक बाउंस होने के मामले में

अदालत ने कहा कि अदालत आदेश की जानकारी होने के बाद भी चारों आरोपी अदालत में पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी वारन्ट जमानती में नहीं बदला जा सकता।

डब्ल्यू.टी.पी. के प्रबंध निदेशक अनूप बरतरिया, रुचि बरतरिया, विरेन्द्र बरतरिया और सरोजनी बरतरिया के गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

अज्ञान जैसा शत्रु दूसरा नहीं। —चाणक्य

राजस्थान में निवेश कैसे बढ़े?

प्रत्येक सरकार यह चाहती है कि उसके प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जाए ताकि न केवल राज्य को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने हेतु राजस्व प्राप्त हो अपितु नागरिकों को रोजगार भी मिले। गत कुछ वर्षों से बेरोजगारी चरम पर है, जिसके कारण उद्योगों में निवेश का महत्व पहले की अपेक्षा बढ़ा है।

निवेश कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्थानीय उद्योगों द्वारा, अन्य राज्यों के निवेशकों द्वारा एवं विदेशी निवेश। जहां विदेशी निवेश को आकर्षित करने का महत्व है वहीं स्थानीय स्तर पर निवेश के द्वारा भी रोजगार की विपुल संभावना बढ़ाई जा सकती है।

राज्य में निवेश को तीव्र गति से बढ़ाने की आवश्यकता को अनुभव करते हुए ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेतृत्व संभालते ही इस क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया है। इसी दृष्टिकोण से "राजिग राजस्थान, इन्वेस्टमेंट समिट" का आयोजन जयपुर में 9 से 11 दिसंबर, 2024 तक किया जा रहा है। इसकी तैयारी के सिंगलिसले में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के कई दल विभिन्न देशों जैसे जापान, कोरिया, सिंगापुर, यू.ए.ई., अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों का दौरा कर चुके हैं। इन्होंने वहां के प्रमुख उद्योगपतियों से चर्चा की। विदेशी निवेश बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जहां तक निवेश का प्रश्न है, वह विदेश के अलावा, भारत के विभिन्न राज्यों से भी आमंत्रित किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान के उद्योगियों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यहां से निकले हुए प्रमुख उद्योगपतियों में एल.एन.मिसल, बिरला, बांगड, सिंघानिया पिरामल, बजाज समिलित हैं।

निवेश समिट के लिए कुछ दिनों से जयपुर शहर को सजाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों पर पौधों के गमले रखे जा रहे हैं। जो अच्छी-खासी सड़के हैं, उन पर भी दोबारा कारपेटिंग किया जा रहा है। सड़क के आसपास के क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हें साफ-सुथरा करने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि यह काम विशेषकर उन्हीं स्थानों पर किया जा रहा है, जहां से 'राजिग राजस्थान' में भाग लेने वाले विदेशी एवं भारतीय निवेशकों को ले जाया जाएगा। सरकार को यह पता होना चाहिए कि आज के मीडिया के युग में विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले व्यक्ति को जयपुर की वास्तविक स्थिति की जानकारी है। इस आलेख में हम यह प्रयास करेंगे कि निवेश के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंड क्या हैं?

सम्मेलन आयोजित करना और सम्मेलन के दिनों में जयपुर शहर को रंग रंगीन कर चमका देने से विदेशी मेहमान, अल्प समय के लिए प्रभावित भले ही हो जाएं, किंतु इससे निवेश नहीं आता है। यदि केवल एम.ओ.यू. करने से राज्य में निवेश आना होता तो अब तक कई सौ लाख करोड़ का निवेश, राजस्थान में हो चुका होता। सरकार को यह जानकारी आवश्यक करनी चाहिए कि अब तक हुए निवेश सम्मेलनों में कुल कितनी राशि के एम.ओ.यू. हुए और उनमें से कितने वास्तव में धरातल पर उतरे?

"राजिग राजस्थान, इन्वेस्टमेंट समिट" से पूर्व, देश-विदेश में कई प्री समिट आयोजित हो चुकी हैं जिनमें 5 लाख करोड़ से अधिक के एम.ओ.यू. पहले ही हो चुके हैं। वास्तव में, निवेशकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है एवं छोटे-छोटे कार्यों के लिए कितना परेशान होना पड़ता है, उस पर निर्भर करता है कि वे राज्य में निवेश करेंगे अथवा नहीं? इस हेतु वे वर्तमान में कार्यरत उद्योगों के अनुभव को भी दृष्टित रखते हैं। सरकार के विभाज्य जहां एक ओर देश-विदेश से नया निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रयासरत है, वहीं पूर्व में जो निवेशक उद्योग लागे चुके हैं, उनके साथ "धर की मुर्गी दाल बराबर" जैसा व्यवहार करते हैं। सरकार को यह समझना होगा कि निवेश कार्य राज्य के अंदर से आए, अन्य राज्यों से अथवा विदेश से, सबके साथ समान रूप से परिभाषा पूर्ण व्यवहार होना चाहिए।

सरकार ने हाल ही में निवेश आकर्षित करने हेतु कई नीतियां जारी की हैं। एक और जहां नए उद्योगों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, वहीं वर्तमान में कार्यरत उद्योगों के लिए भी काम करना, सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता है।

नीतियों में निरंतरता भी, निवेश को आमंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सत्ताधारी दल के बदलने से दीर्घकालीन नीतियों में किसी प्रकार का अंतर न आए, यह सुनिश्चित करना होगा। अन्यथा, निवेशक, निवेश करने के पश्चात्, स्वयं को ठगा सा महसूस करेगा।

राज्य की नौकरशाही को, उद्योगियों के प्रति मित्रवत व्यवहार की संस्कृति अपनाने की जरूरत है। सरकार के सब संबंधित विभागों का एक ही सूत्र वाक्य होना चाहिए, "अच्छा व्यवहार, तत्परता"। उद्योगियों के काम, तत्काल, बिना किसी परेशानी के करने की आवश्यकता है।

निधियों का सरलीकरण भी किया जाना आवश्यक है। सभी सरकारें, समय-समय पर 'सिंगल विंडो सिस्टम' की बात करती रही हैं, किंतु वास्तविकता में इसे धरातल पर लागू होते हुए बहुत कम ही देखा गया है। सिंगल विंडो का अर्थ ही यह है कि निवेशक को, अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ें और उनको और से यह काम राज्य सरकार का मनोत आधिकारी करे।

इस बार सरकार ने एक अच्छा कदम यह उठाया है कि प्रत्येक देश एवं अन्य प्रदेश से निवेश को आकर्षित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। इनकी जिम्मेदारी होगी कि वे एम.ओ.यू. करवाने से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जयपुर में जिस प्रकार के सुधार कार्य एवं शहर को बेहतर बनाने के कार्य राजिग राजस्थान समिट के लिए किए जा रहे हैं, वैसे ही लगातार होते रहें। यदि समिट के बाद पुनः हालात पहले जैसे ही हो जाएं, तो यह निवेशकों के साथ एक प्रकार से धोखा ही होगा और इससे राज्य की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

इन अधिकारियों को यह भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि वे वर्तमान में कार्यरत उद्योगों की समस्याओं का तत्काल निवारण से निस्तारण करावें।

निवेश इस पर भी निर्भर करता कि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति कैसी है एवं 'ईजऑफ लिविंग' कितना है? जयपुर शहर में, यदि कोई पूरा भ्रमण कर ले, तो उसे स्पष्ट हो जाएगा कि सार्वजनिक मार्गों पर विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण और अतिक्रुत वाहनों के कारण कितनी कठिनाई होती है? जिस प्रकार, विभिन्न क्षेत्रों में गंगा की देर लगे रहते हैं, उन्हें देखकर कोई भी निवेशक बार-बार राज्य में निवेश करने से पहले सोचेगा। उद्योगों में कार्य करने वाले अधिकारी, कई बार अलग-अलग राज्यों से आते हैं एवं रहने के लिए उपयुक्त वातावरण यदि नहीं पाते हैं, तो वे यहां काम नहीं करना चाहते हैं। उपयुक्त विशेषज्ञों का अभाव निवेशकों को हतोत्साहित करता है।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जयपुर में जिस प्रकार के सुधार कार्य एवं शहर को बेहतर बनाने के कार्य राजिग राजस्थान समिट के लिए किए जा रहे हैं, वैसे ही लगातार होते रहें। यदि समिट के बाद पुनः हालात पहले जैसे ही हो जाएं, तो यह निवेशकों के साथ एक प्रकार से धोखा ही होगा और इससे राज्य की छवि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

तत्काल काम करने और अच्छे व्यवहार की संस्कृति ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक अधिकारी में परिलक्षित होनी चाहिए। वर्तमान में जो लोग यहां पर उद्योग चला रहे हैं, उनकी समस्याओं का तत्काल निवारण किया जाए तो वे राज्य के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण करने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। प्रबंध निदेशक, रीको के रूप में कार्य करते हुए मैंने यह अनुभव किया कि बहुत छोटे-छोटे कामों के लिए यदि अधिकारी, तत्परता से सहयोग करें तो उद्योगी बहुत राहत महसूस करते हैं।

राजस्थान में निवेश लाने समय, इस बात पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि केवल बहुत बड़ी पूंजी के निवेश से ही रोजगार उत्पन्न नहीं होता। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जितनी भूमि राज्य द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, उस पर प्रति एकड़ कितना रोजगार उपलब्ध होगा? सबसे प्रमुख समस्या, राज्य के समक्ष बेरोजगारी की है, और उसे दूर करने में वही उद्योग अधिक सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जहां पर रोजगार की अधिक संभावनाएं हैं। हजारों करोड़ निवेश करके भी यदि नाम मात्र का रोजगार मिले, तो उससे, निवेश के आंकड़ों में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसे रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। एक समीकरण बनाना होगा, जिसमें भूमि, पूंजी एवं रोजगार तीनों अवयवों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना होगा। राज्य को सस्ती भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक है। उद्योग लगाने में भूमि की लागत कम होनी चाहिए। उन लोगों को हतोत्साहित करना होगा जो केवल भूमि में निवेश करना चाहते हैं और जिनकी रुचि उद्योग लगाने में नहीं है।

मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभालते ही औद्योगीकरण में तेजी लाने के महत्व को समझा है और इस हेतु उन्होंने सघन प्रयास प्रारंभ किए हैं। इन प्रयासों को फलीभूत करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नौकरशाही, उद्योगपतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए। पत्रावली पर कुछ भी निर्णय लेते समय, यह प्रश्न पूछना, अधिकारियों को छोड़ना पड़ेगा कि "इससे मुझे क्या लाभ होगा?" जो अधिकारी इस आधार पर निर्णय लेते हैं, वे प्रकरणों को तब तक लंबित रखते हैं जब तक कि उनसे कोई संपर्क न कर ले और उनकी 'इच्छाओं' की पूर्ति न कर दे। अधिकारियों द्वारा फाइल पर कुछ भी निर्णय लेते समय केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि "इससे राज्य और राज्य की जनता को किस प्रकार से लाभ मिलेगा?"

जो अधिकारी 'अच्छा व्यवहार, तत्परता' के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उन्हें निवेशकों से सार्वजनिक रूप से सराहना मिलती है। इसका अनुभव मैंने, स्वयं ने, रीको के प्रबंध निदेशक पद पर 3 वर्ष तक कार्य करते समय किया था। आज भी, मैंने जापानी उद्योगों के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों तथा स्थानीय उद्योग संघों द्वारा लिखे गए, उन सराहना वाले पत्रों को सम्हाल रखा है, जो उन्होंने बहुत समय से लंबित महत्व पूर्ण समस्याओं के तत्काल निस्तारण होने पर लिखे थे।

आशा है, नौकरशाही की सकारात्मक सोच और सहयता करने की मानसिकता से, मुख्यमंत्री जी के प्रयास अवश्य ही फलीभूत होंगे। सरकार से यह भी अपेक्षा है कि वह समय-समय पर एक रिपोर्ट राज्य के समक्ष प्रस्तुत करे कि जितने एम.ओ.यू. हुए, उनमें से कितने वास्तव में धरातल पर उतरे और कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ?

"राजिग राजस्थान, इन्वेस्टमेंट समिट" के सफल आयोजन हेतु राज्य सरकार को शुभकामनाएं। आशा है, इसके परिणाम स्वरूप, राज्य की जनता को दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा एवं वे तीव्रता के साथ प्रगति के पथ पर बढ सकेंगे। यह संभव है, यदि इस आलेख में दिए गए कुछ सुझावों पर ध्यान दिया जा सके।

—राजेन्द्र भागवत, पूर्व आई.ए.एस. पूर्व प्रबंध निदेशक, रीको



महावीर सिंह

13 से 15 मई 2022 तक, कांग्रेस ने एक बड़ा चिंतन कार्यक्रम उदयपुर में रखा था। उस चिंतन में निकली चिंताओं व आगे के रौंड मैप के बारे में काफी चर्चाएं हुईं।

इसी प्रकार से 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इस पर भी खूब चर्चाएं हुईं।

इन दोनों ही घटनाक्रमों के सम्बंध में 12 मई 2022 व 16 दिसम्बर 2022 के राष्ट्रदूत में इस लेखक के दो लेख छपे थे। इन लेखों के कुछ अंश, कांग्रेस की स्थिति के सम्बंध में आज भी उतने ही प्रसंगिक हैं।

(12 मई 2022 के राष्ट्रदूत में प्रकाशित—कांग्रेस का चिंताओं पर चिंतन—नव संकल्प शिबिर) लेख के कुछ अंश—

13 से 15 मई को भारत की ग्रन्थऑल्ट पार्टी का एक चिंतन शिबिर, राजस्थान के सुंदर शहर उदयपुर में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के 500 के करीब बड़े कांग्रेसी नेता भाग लेंगे।

—राज्य व्यवस्था की लोकात्मिक प्रणाली में सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, तभी सरकारी की ममानियों, गलत जन विरोधी नीतियों पर अंकुश लगने की संभावनाएं बनती हैं। लोकतंत्र की मूल अवधारणाओं में विश्वास करने वाले सत्ता पक्ष के भी बहुत से बड़े नेता मानते हैं कि एक सशक्त विपक्ष बहुत आवश्यक है किंतु यह काम सत्ता पक्ष को तो नहीं करना है न?

—वर्तमान में विपक्ष, बिना समन्वय के एक पूर्णतः निष्क्रिय, कांतिविहीन, दिशाविहीन जमावड़ा सा लगता है— स्वर्गीय राजीव गांधी व कांग्रेस के प्रयास से संवैधानिक संसोधनों के जिये सत्ता नीचे गांवों, पंचायत समितियों—मंडलों, जिला परिषदों, स्थानीय निकायों तक पहुंचाने का रस्ता खुला— राज्यों में बड़े मठाधीस नेता इस प्रयास को पूर्ण रूप से सफल नहीं होने दे रहे—

—स्वतंत्रता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

—राजस्थान की बात करें तो— जागीरों की समाप्ति, —कृषि कार्य कर रहे थे उन्हें खातेदार मालिक बना दिया। एस.सी.एस.टी. के—

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

गुणवत्ता आंदोलन के समय से लेकर संबंधित उद्योग में उत्पादन प्रारंभ होने तक की सारी बाधाओं को दूर करने का कार्य करें। यह अच्छी पहल है। आशा की जानी चाहिए कि अधिकारी गण पूरे मनोयोग से अपने दायित्व को निभाएं।

कार्य प्रणाली व निर्णय प्रक्रिया बताती है, सत्ता की आकांक्षी कांग्रेस गलतियों से कुछ सीखना चाहती नहीं— (भाग-1)

उत्थान की नीतियां, कार्यक्रम व कानून बनाया— न्यूनतम आवश्यकताओं—रोटी, कपड़ा और मकान— को केंद्र में रख कर मिनिमम नीड प्रोग्राम— —सिंचाई—सड़क—कृषि विकास—विद्युत परियोजनाएं बनाईं, पूर्ण की, उद्योगीकरण की मजबूत नीव रखी, डेजर्ट डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के चलाए। बैंकों से ग्रामीणों को— आवश्यकताओं के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ी। बंधक श्रमिक उन्मुक्ति—कृषि जोतों पर सीलिंग के तथा शिक्षा का—सूचना का— खाद्य सुरक्षा के अधिकार—मनरेगा कानून बनाये और लागू किये। यह कांग्रेस राज के बिखरे हुए बेनेफिसियरी युग थे।

—किन्तु कांग्रेस ने बड़ी गलतियां भी की, जनता में सजा दी, पुनः सत्ता भी दी। कांग्रेस ने पुनः कुछ गम्भीर गलतियां की और उनकी जो सजा जनता ने दी, वह अभी कांग्रेस भुगत रही है। 2014 से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर है और राज्यों में भी जनानाथर लगातार सिकुड़ रहा है।—भाजपा ने चतुराई से बड़े भिन्न लाभार्थी युग बना दिये, यह उसके नेतृत्व कुशलता का प्रतीक है।—

कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। वर्तमान में वह विपक्ष का दायित्व निभाये। सत्ता प्राप्त के लिए जनता के समक्ष, गांव-मोहल्ले तक अपनी नीतियां, कार्यक्रम पहुंचाने। (क्या ऐसा होता दिख रहा है??) —कांग्रेस को सबसे बड़ी कमी थी कि उसने अपनी योजनाओं, कार्यक्रमों, कानूनों का प्रचार-प्रसार व सही क्रियान्वयन नहीं किया और उनका यथोचित श्रेय नहीं ले पाई।

—वर्तमान सत्ता पक्ष जिस सिद्धत से अपने कार्यक्रमों के सम्बंध में ऐसा करता है, कांग्रेस या अन्य दलों को सीखना चाहिए।

—कांग्रेस को—हमें न सिखाये, हमे उनसे सीखने की जरूरत नहीं—की मनसिकता को त्यागने की आवश्यकता है।

—कांग्रेस को जनता को यह बताना, समझना होगा कि कांग्रेस सत्ता पक्ष से ज्यादा अच्छे प्रकार से जनता की कठिनाइयों को समझती है और समाधान की बेहतर योजनाएं, कार्यक्रम चलाएगी।

—जनता उस पर क्यों, कैसे विश्वास करे?? इसके लिए कांग्रेस के नेतृ अपने अचार-व्यवहार से, अहंकार त्याग कर-राजशाही लाइफ स्टाइल छोड़ कर और जनता के मध्य जाकर, छोटी-छोटी सभाएं, संगोष्ठियां कर, समझाइस कर जनता के गले यह बात उतरी।

—कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए जा रहे, जिन पर स्पष्ट नीतियां, कमिटमेंट की आवश्यकता है। अत्यधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों से हटा कर कृषि का विविध करण और किसानों द्वारा उसे अपनाए जाने पर कुछ समय के लिए उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई की नीति, एमएसपी को विधिक अधिकार बनाने और क्रियान्वयन।

गत 20 वर्षों में एमएसपी नहीं मिलने से देश के किसानों को लगभग 45 लाख करोड़ रु का नुकसान हुआ है। इस कारण उन पर कर्जा बढ़ा है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट नीति किसानों को बताएं—कृषि इनपुट्स की कोस्ट्स का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरह त्रैमासिक आधार प्राकलन व तदनुसार एमएसपी का रेगुलर पुरावावलीकरण—

कृषि बीमा योजना की समीक्षा, सरलीकरण — सेटेलाइट इमेजरीज के आधार पर त्वरित आकलन व भुगतान श्रमिक कल्याण व सामाजिक सुरक्षा नीतियां

राजकीय उपक्रमों में भले ही सरकारी शेयर होल्डिंग कम करके उन्हें चलाने का दायित्व प्राइवेट हाथों में दे दे किन्तु उनकी स्थायी भूयुक्तता पर 100 प्रतिशत स्वामित्व सरकारी रहे, सेनाओं और अन्य शस्त्र बलों की भूमियों का, निजी व्यवसायिक, आवासीय, उद्योगिक कार्यों हेतु उपयोग निषेध हो।

सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया यथावत जारी रखी जाए—लघु उद्योगों के सम्बंध में नीति—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

लौमियर प्रोजेक्ट्स को छोड़कर यदि, राज्य प्राइवेट कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण करे तो भूमिधारकों की मांग पर मुआवजे के नकद भुगतान की एवज में मुआवजे की कुछ हिस्से के मूल मूल्य पर कम्पनी शेयर प्राप्त करने का हक—

अपनी समन्वित नीति साफ करनी होगी—लोककपाल संस्था को सशक्त करने—भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस—कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर जिस से जनता विश्वास करे—धंदे के लिए राजनीति करने वालों से पीछा छुड़ाओ—महिलाओं को निर्वाचन वाली संस्थाओं और सरकारी नोकरीयों में 50 प्रतिशत आरक्षण

—मध्यम जातियां—: किसी समय यह कांग्रेस की रीढ़ हुआ करती थी किन्तु कांग्रेस में निहित स्वार्थियों ने इन जातियों को सत्ता में सम्मानपूर्ण भागीदारी नहीं दी और शनः शनः वे जातीयां कांग्रेस से विमुख हो गईं। यूपी में चौधरी चरण सिंह के कांग्रेस छोड़ने के उपरांत व जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी तथा वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के नारे जनता के मानस पर छा गए और उतरी गयान में कांग्रेस का पतन प्रारम्भ हो गया।

इन जातियों को, राज में पर्या

सेवा भाव से योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अंत्योदय के संकल्प के साथ समाज के वंचित वर्ग के कल्याण हेतु समर्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्ग को मिलना सुनिश्चित हो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सेवाभाव से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पंचित के व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे तथा अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न ले पाए, क्योंकि इससे पात्र व्यक्ति के हितों पर कुटाराघात होता है। शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता तय कर चरणबद्ध रूप से किया जाए। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पथर तोड़ने एवं पीसने के कार्य वाले स्थानों एवं खदानों पर निर्धारित गार्डइलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराए ताकि सिलिकोसिस रोग पर नियंत्रण किया जा सके।

- राज्य में 90 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए 1500 करोड़
- मुख्यमंत्री ने की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई निर्णय किए हैं। राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की राशि को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि

आश्रय से वंचित घूमंतू समुदाय के लोगों के लिए घूमंतू आवासीय योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के दिव्यांग नागरिकों को कुत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, 2 हजार युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने के लिए स्कूटी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ कर 5 हजार रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार लगभग 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दे रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की पात्रता व उनसे जुड़े रिकॉर्ड का नियमित रूप से सत्यापन करें और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे पेंशनर्स की मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर संबंधित कार्मिकों को जिम्मेदारी तय की जाए।

महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट व ब्रज चौरासी यात्रा पर प्रस्तुतिकरण



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष सोमवार को पर्यटन भवन में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष अंकार सिंह लखावत तथा पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में 'महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट' और 'ब्रज चौरासी यात्रा की' कॉन्सेप्ट प्लान और पार्लियामेंट्री रिपोर्ट बनाने के लिए प्राप्त निविदाओं का कन्सल्टेन्ट्स व आर्किटेक्स्ट्स ने प्रस्तुतिकरण दिया।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के समक्ष सोमवार को पर्यटन भवन में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष अंकार सिंह लखावत तथा पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में 'महाराणा प्रताप ट्यूरिस्ट सर्किट' और 'ब्रज चौरासी यात्रा की' कॉन्सेप्ट प्लान और पार्लियामेंट्री रिपोर्ट बनाने के लिए प्राप्त निविदाओं का कन्सल्टेन्ट्स व आर्किटेक्स्ट्स ने प्रस्तुतिकरण दिया।

विदुवार चर्चा की गई। दिया कुमारी ने प्रस्तुतिकरण के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज विभिन्न एजेंसियों की ओर से प्रस्तुतिकरण दिए गए हैं। इस आधार पर विदुवार नियोजित रूप से योजना बनाकर काम किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन विभाग की 145 करोड़ की दो बड़ी योजनाओं को मंजूरी पर पत्रकारों के समक्ष केन्द्रीय पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का आभार जताते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों की विश्वस्तरीय

बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत अमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि जयपुर में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित करने को लक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना के क्रियान्वयन का काम चल रहा है।

नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली जानी

जयपुर। जी-20 में भारत सरकार के निजी प्रतिनिधि और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया।



जी-20 में भारत सरकार के निजी प्रतिनिधि और नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने जयपुर फुट की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया।

जयपुर फुट की निर्माता संस्था भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बी.एम.वी.एस. एस.) के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डी.आर. मेहता, सचिव भूपेन्द्र राज मेहता तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस. बिस्सा ने अमिताभ कान्त का स्वागत किया और जयपुर फुट की निर्माण विधि की जानकारी दी। अमिताभ कान्त ने कहा कि बी.एम.वी.एस.एस. निस्वार्थ भाव से विकलांगों को सेवा कर रही है और यह विश्व में अपनी तरह की अद्वितीय संस्था है, जिसने सारे भारत और विश्व भर में जयपुर फुट प्रचलित कर विकलांगों की सेवा की। उन्होंने कहा कि डी.आर. मेहता ने आई. ए.एस. अधिकारी रहते हुए न सिर्फ बी.एम.वी.एस.एस. की स्थापना कर एक अनुकरणीय संस्था बनाने में योगदान दिया बल्कि इस विश्व भर में ख्याति भी दिलाई।

फुट जैसे गुणवत्ता वाले उपकरण और अधिक प्रचलित हों और अधिक से अधिक विकलांगों द्वारा अपनाये जाये। अमिताभ कान्त ने दस विकलांगों के पुर्नवास और उन्हें जयपुर फुट लगाने के लिए योगदान दिया।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ यूसीसी, कृषक मित्र भाजपा सरकार, अवैध धर्मोन्तरण और राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यों पर चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि केन्द्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार लगातार जनहितैथी कार्यों को कर रही है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा जहां समान नागरिकता कानून का समर्थन किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा ईआरसीपी योजना को मूर्त रूप देकर लाखों किसानों के लिए सिंचाई

परियोजना के प्रारूप 2015-16 में तैयार किया गया, इसके बाद प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अटकाने का काम किया हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता में आने के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस जीवन दायनी परियोजना पर कार्य शुरू किया और अब इसका शिलान्यास होगा। परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेशभर से करीबन तीस लाख लोगों की उपस्थिति रहेगी। इससे जहां पीने के पानी की

समित में न्यूनतम होगा प्लास्टिक का उपयोग

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नए संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने सोमवार को पांचवा संकल्प लेते हुए राजजिंज राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने का निश्चय किया है।

प्रधानमंत्री विशाल जनसभा में ई.आर.सी.पी. परियोजना का शिलान्यास करेंगे : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नई दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों के साथ यूसीसी, कृषक मित्र भाजपा सरकार, अवैध धर्मोन्तरण और राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यों पर चर्चा की। राठौड़ ने कहा कि केन्द्र और राजस्थान में भाजपा की सरकार लगातार जनहितैथी कार्यों को कर रही है। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा जहां समान नागरिकता कानून का समर्थन किया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा ईआरसीपी योजना को मूर्त रूप देकर लाखों किसानों के लिए सिंचाई

परियोजना के प्रारूप 2015-16 में तैयार किया गया, इसके बाद प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को अटकाने का काम किया हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता में आने के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार के साथ मिलकर इस जीवन दायनी परियोजना पर कार्य शुरू किया और अब इसका शिलान्यास होगा। परियोजना के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेशभर से करीबन तीस लाख लोगों की उपस्थिति रहेगी। इससे जहां पीने के पानी की

समस्या का समाधान होगा, वहीं सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त जल भी मिलेगा। राठौड़ ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष को सकारात्मक कार्यों में अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। हालांकि विपक्ष का कार्य आरोप प्रत्यारोप लगाना ही रह गया है। भाजपा ने प्रदेश की जनता के लिए ईआरसीपी, पीकेसी के साथ जवाई पुर्नभरण योजना पर भी कार्य शुरू किया। इसके साथ प्रदेश के बांध, नहरों के पुर्नभरण सहित अन्य विकास के कार्यों को प्राथमिकता से किया जा रहा है।

'मस्जिदों को मंदिर बता कर झूठे केस दायर किये जा रहे हैं'

जयपुर। राजस्थान के अजमेर और उत्तर प्रदेश के संभल मामले को लेकर आज मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी मोडिया से रूबरू हुए। मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी ने कहा कि धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंचाने का धिनीना काम किया जा रहा है। देश के आपसी सद्भाव को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिदों को मंदिर बता कर अदालत में झूठे केस दायर किया जा रहे हैं। सर्वे के नाम पर मस्जिदों के स्ट्रेट्स को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के बयाने सर्वे करा कर देश का माहौल खराब किया गया। केन्द्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लाकर मुस्लिम को जमीनों को हड़पना चाहती है। संभल मामले में जिस तरह से मस्जिद को बचाने अथवा हक की आवाज को उठाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ इस

■ अजमेर दरगाह और संभल मामले को लेकर मुस्लिम संगठनों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

कोशिश बताया। ऐसी याचिकाओं को खारिज किया जाए ताकि देश की गंगा-जमुनी तटजोब और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे।

पुलिस अधिकारी बताए बिना अपराध क्यों की गिरफ्तारी : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अपराधिक मामले में सरकार की वकील को कहा है कि संबंधित पुलिस अधिकारी का शपथ पत्र पेश कर बताए कि अब अनुसंधान में आईपीसी की धारा 326 के तहत अपराध साबित नहीं हुआ और अन्य अपराध जमानती प्रकृति के हैं तो याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी क्यों किया गया। जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश पूजा शर्मा व सौरभ की याचिका पर दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीके शर्मा ने अदालत को बताया कि सार्वक शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में पुलिस ने गलत तरीके से उसके साले याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सार्वक के परिजनों ने अपने प्रभाव का

दुरुपयोग करते हुए पुलिस को दबाव में लेकर याचिकाकर्ता को झूठे मामले में गिरफ्तार कराया दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति सार्वक शर्मा ने उसके साथ मारपीट और अप्रधत्ता कर उसे घर से निकाल दिया था। इस पर उसने अपने भाई सौरभ को बुलाया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उनके खिलाफ ही 8 दिसंबर, 2023 को जवाहर नगर थाने में मारपीट व सशस्त्र हमला सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज करा दिया। वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जबकि मामले में धारा 326 के तहत अपराध साबित नहीं हुआ और अन्य धाराएं जमानती अपराधों से जुड़ी हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का शपथ पत्र पेश करने को कहा है।

बजरी की अवैध सप्लाई के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी

जयपुर। प्रदेश में बजरी की बढ़ती दरों के लिए राज्य सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। शहर में बजरी मंडियों में अवैध बजरी सप्लाई को लेकर व्यापारी लामबंद हो गए हैं।

नदी क्षेत्र में वैध बजरी खनन के लिए समय पर लीज जारी नहीं की जा रही है जिसके कारण अवैध बजरी खनन को बढ़ावा मिल रहा है। यह बात ऑल राजस्थान बजरी टुक ऑपरेटर वैलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने आरोप लगाया कि अवैध बजरी खनन को बढ़ावा देने के लिए पुलिस प्रशासन वैध रक्त्वा के साथ बजरी परिवहन करने वाले टुक ऑपरेटर्स को परेशान कर रही है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध बजरी खनन व परिवहन बंद नहीं किए जाने पर सभी टुक ऑपरेटर्स बजरी परिवहन बंद कर देंगे। नवीन शर्मा ने कहा कि अवैध

अगर प्रशासन ने रोक नहीं लगाई तो सप्लाई बंद कर देंगे : नवीन शर्मा

बजरी परिवहन को बंद करवाने के लिए लाइसेंस धारक व्यापारियों ने इस संबंध में आज खान विभाग के अधिकारियों को पत्र देकर इसे रकवाने की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर वैध बजरी खनन क्षेत्रों से खनन बंद करने और सप्लाई रोकने की चेतावनी दी है। टॉक, सवाई माधोपुर एरिया में कई ब्लॉक में अवैध बजरी का खनन हो रहा है। उन खनन एरिया के आसपास रिमोट एरिया (गांवों में) बजरी के अवैध स्टॉक बनाए जा रहे हैं। इन स्टॉक में अवैध तरीके से खनन करके बजरी एकत्रित किया जा रहा है उसे जयपुर शहर

शर्मा ने बताया कि यूनिजन ने खान विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर इन अवैध स्टॉक करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की है। इसके साथ ही हमने प्रशासन ने जल्द ही दूसरे वैध स्टॉक (टॉक, सवाई माधोपुर एरिया में) को भी शुरू की मांग की है। अगर सरकार 10-15 दिवस में इन अवैध बजरी परिवहन और स्टॉक करने वालों पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो मजबूरन सभी टुक ऑपरेटर्स जो वैध लीज से बजरी लाकर सप्लाई कर रहे हैं उसे बंद करना पड़ेगा।

जयपुर। राज्य सरकार राजकीय कार्यालयों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग के 9 अनुशासनहीन कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय किया है। यह निर्णय राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 53 (1) के प्रावधान के तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित रिज्यू कमेटी एवं प्रशासनिक सुधार की आज्ञानुसार गठित उच्च स्तरीय स्थायी समिति की अनुशंसा पर किया गया है। इन कार्मिकों ने घोर लापरवाही करते हुए अनुशासनहीनता एवं अनियमितताएं की थी, जिसके लिए पूर्व में उन्हें कई बार दंडित भी किया गया था।

मुख्यमंत्री ने अनुशासनहीन नौ कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी

जयपुर। राज्य सरकार राजकीय कार्यालयों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस विभाग के 9 अनुशासनहीन कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय किया है। यह निर्णय राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 के नियम 53 (1) के प्रावधान के तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित रिज्यू कमेटी एवं प्रशासनिक सुधार की आज्ञानुसार गठित उच्च स्तरीय स्थायी समिति की अनुशंसा पर किया गया है। इन कार्मिकों ने घोर लापरवाही करते हुए अनुशासनहीनता एवं अनियमितताएं की थी, जिसके लिए पूर्व में उन्हें कई बार दंडित भी किया गया था।

भजनलाल सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करें : डॉ. प्रेमचंद बैरवा

जयपुर (कासं)। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को शासन सचिवालय में राजस्थान सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, आयुर्वेद विभाग की तैयारियों की समीक्षा की।



उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की।

बैठक में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, योजनाओं का आमजन तक उचित प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने प्रत्येक विभाग को अपनी एक वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते हुए लघु वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) का निर्माण करने और इस वृत्तचित्र को विभागीय वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा प्रमुख चौराहों पर स्थापित डिजिटल एलईडी पैनलों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि

विभागीय उपलब्धियों के साथ-साथ प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख स्थानों पर विशेष बอร์ด्स लगाए जाएं। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षा संकुलों के समीप, आयुर्वेद विभाग द्वारा चिकित्सालयों के निकट, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा परिवहन कार्यालयों के आस-पास तथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा

प्रमुख बस स्टैंड के समीप एवं विभागीय प्रमुख भवनों पर बोर्डिंग्स स्थापित किए जाएं।

■ उपलब्धियों के शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया और प्रमुख चौराहों पर डिजिटल एलईडी पैनल पर प्रदर्शित होंगे

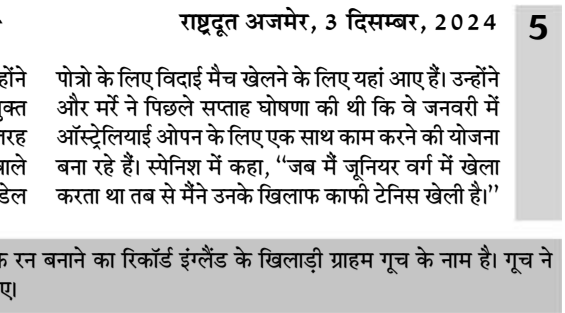
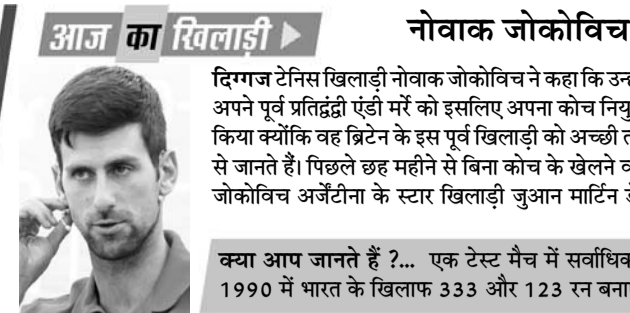
■ 'जून 2025 के बाद निर्मित एन-2 और एन-3 श्रेणी के ट्रकों के कैबिन में चालकों की सुविधा के लिए शुरू होगी वातानुकूलन प्रणाली'

■ राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ के सवाल के जवाब में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दी जानकारी

को प्रदर्शित करते हुए रंगीन सचित्र बुकलेट का मुद्रण एवं जन सामान्य तक वितरण सुनिश्चित कर ताकि अधिकतम जन-जन तक विभागीय उपलब्धियों की जानकारी पहुंच सके। डॉ. बैरवा ने कहा कि विभागीय उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रमुख समाचार पत्रों, ऑडियो एवं वीडियो फिल्म के माध्यम से आमजन को जागरूक किया जाए।

बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अध्यक्ष शुभा सिंह, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की शासन सचिव डॉ. आरूषी अजय मलिक, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की आयुक्त एवं सड़क सचिव शुचि त्र्यागी, रोडवेज प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा, मीडिया सलाहकार आनंद शर्मा सहित अन्य उच्चाधिकारी मौजूद थे।

राठौड़ बताया कि केन्द्र सरकार देश में निजी टुक वाहनों में चालकों की कार्य कुशलता बढ़ाने के साथ चालक की थकान की समस्या का समाधान करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जून 2025 के बाद निर्मित एन-2 और एन-3 श्रेणी के वाहनों में चैसिस निर्माताओं द्वारा निर्धारित आईएस के अनुसार वातानुकूलन प्रणाली के लिए एक अनुमोदित किट की आपूर्ति भी की जाएगी, जिससे बांटी तैयार करने वालों को किट लगाने की सुविधा हो सके। इससे टुक चालकों के कैबिन में वातानुकूलित सुविधा शुरू हो जाएगी।



भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह लॉस एंजिल्स में होने वाले अगले ओलिंपिक खेलों के लिए उसकी तैयारी की शुरुआत है।
- रानी रामपाल

पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की जीत की तैयारियों के बारे में बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

नोवाक जोकोविच

राष्ट्र अजमेर, 3 दिसम्बर, 2024 5

दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कहा कि उन्होंने अपने पूर्व प्रतिद्वंद्वी एंडी मरे को इसलिए अपना कोच नियुक्त किया क्योंकि वह ब्रिटेन के इस पूर्व खिलाड़ी को अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले छह महीने से बिना कोच के खेलने वाले जोकोविच अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी जुआन मार्टिन डेल

ग्व्या आप जानते हैं? ... एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाड़ी ग्राहम गृच के नाम है। गृच ने 1990 में भारत के खिलाफ 333 और 123 रन बनाए।

पोत्रो के लिए विवाद मैच खेलने के लिए यहां आए हैं। उन्होंने और मरे ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वे जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिए एक साथ काम करने की योजना बना रहे हैं। स्पेनिश में कहा, "जब मैं जूनियर वर्ग में खेला करता था तब से मैंने उनके खिलाफ काफी टेनिस खेला है।"

// अगले 3 साल तक भारत और पाकिस्तान मैच दुबई में होने वाले थे // चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर फिर फंसा पैंच! बीसीसीआई ने ठुकराई पीसीबी की मांग



नई दिल्ली, 2 दिसम्बर। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान और भारत एक बार फिर सामने सामने हैं। जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करने के बदले में उसका भी फायदा हो बीसीसीआई ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल, पीसीबी का कहना था कि भारतीय टीम उनके देश नहीं आना चाहती तो आगामी इवेंट्स में पाक टीम भी खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी और उसके लिए भी हाइब्रिड मॉडल लागू किया जाना चाहिए। साफ तौर पर समझते पाकिस्तान की ओर से भारत-पाक मैचों को दुबई में करवाए जाने की मांग रखी गई थी। वहीं अब एक नए खुलासे में कहा गया कि बीसीसीआई ने पाकिस्तान को इस मांग को खारिज कर दिया है। मांगों से भी कि अगले 3 साल तक किसी भी आईसीसी इवेंट में होने वाले भारत और पाकिस्तान मुकाबले को न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया जाए। न्यूट्रल वेन्यू के रूप में दुबई का नाम लिया गया था और इस फॉर्मूला को पहले पार्टनरशिप कहकर

संबोधित किया गया। शुरुआत में इसे हरी झंडी दिखाए जाने की खबरें थीं, लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार भारतीय बोर्ड ने इसे ठुकरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने पहले इस पार्टनरशिप फॉर्मूला में दिलचस्पी दिखाई थी, जिसके तहत अगले 3 साल तक भारत और पाकिस्तान मैच दुबई में होने वाले थे।

रविवार को छुट्टी का हवाला देते हुए बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं सुनाया। वहीं सोमवार और मंगलवार को यूईई में दफ्तर बंद होते हैं। इसी बीच जय शाह ने 1 दिसंबर को आईसीसी चैयरमैन का पद संभाल लिया है। इन सभी घटनाओं के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मामले का फैसला अब भी अंधार में लटका हुआ है। एक पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट के अनुसार पीसीबी के सूत्र ने बताया कि, हमने बिल्कुल उचित समाधान पेश किया था। अब अगर भारत इस फॉर्मूला को स्वीकार नहीं करता है तो वह हमसे उम्मीद ना करे कि हम पब्लिसिटी में अपनी टीम को उनके देश भेजेंगे। अगर भविष्य में भारत में कोई आईसीसी इवेंट होता है तो उसे हमारे खिलाफ मैच दुबई में खेला होगा।

अनुसार पीसीबी के सूत्र ने बताया कि, हमने बिल्कुल उचित समाधान पेश किया था। अब अगर भारत इस फॉर्मूला को स्वीकार नहीं करता है तो वह हमसे उम्मीद ना करे कि हम पब्लिसिटी में अपनी टीम को उनके देश भेजेंगे। अगर भविष्य में भारत में कोई आईसीसी इवेंट होता है तो उसे हमारे खिलाफ मैच दुबई में खेला होगा।

चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर विवाद पर शोएब अख्तर का विवादित बयान इंडिया को वहीं पर मार के आओ...



जाएगा। इसमें भारतीय टीम अपने मैच दुबई में खेलेगी। भारत और पाकिस्तान का मैच भी दुबई में खेला जाएगा। हालांकि, पीसीबी कुछ शर्तों के साथ हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हुआ है। पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि जब भारत में किसी आईसीसी इवेंट का आयोजन होगा तो वो भी अपनी टीम वहां नहीं भेजेंगा। ऐसे में तब भी आईसीसी को वो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में कराना

होगा। हालांकि, इस पर शोएब अख्तर का रुख एकदम अलग है। शोएब अख्तर ने कहा कि, आपको होटिंग राइड्स और रेवेन्यू के लिए पैमेंट किया जा रहा है। ये ठीक है हम समझते हैं। पाकिस्तान का स्टॉप्स भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था जब हम अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करने में सक्षम हैं तो वो आने से मना कर रहे हैं। आईसीसी को हमें हाई रेवेन्यू शेयर करना चाहिए। ये एक अच्छा कॉल है। भविष्य में किसी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम के भारत जाने पर शोएब अख्तर ने कहा कि, जहां तक भारत में खेलने की बात है तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हमारी टीम को वहां जाना चाहिए मेरा हमसा से मानना है कि इंडिया जाओ और उन्हें वहीं मारो हराओ। भारत में खेले और उन्हें वहीं हरा के आओ।

अंडर-19 एशिया कप: भारत ने जापान को 211 रनों से दी शिकस्त

शारजाह, 2 दिसंबर। कप्तान मोहम्मद अमान (नाबाद 122) की शतकीय, आयुष महत्रे (54) और केपी कार्तिकेय (57) की अर्धशतकीय पारियों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने सोमवार को अंडर-19 एशिया कप के आठवें मुकाबले में जापान को 211 रनों से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ भारत के दो मैचों में एक हार और एक जीत के साथ दो अंक हो गये और वह अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है।



340 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जापान की टीम की शुरुआत धीमी रही। हुगो केली और निहार परमार की सलामी जोड़ी ने संभल कर खेलते हुए पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। 14वें ओवर में हार्दिक राज ने निहार परमार (14) को आउट भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद कप्तान कोजी आबे (शून्य) को केपी कार्तिकेय ने बोल्ट कर भारत के लिए दूसरा विकेट झटका। काजूमा काटो-स्ट्रेफर्ड (आठ) पर रनआउट हुये। 33वें ओवर में हार्दिक राज ने हुगो केली को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। केली ने 111 गेंदों में छह चौके लगाते हुये (50) रनों की पारी खेली। इसके बाद चार्ल्स हिंजे को छोड़कर जापान का कोई भी

बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे अधिक देर तक नहीं टिक सका। चार्ल्स हिंजे ने 68 गेंदों में (नाबाद 35) रन बनाये। तिमूती मुरे (एक), आदित्य फाडके (नौ) और केवाई लेक (एक) रन बनाकर आउट हुये।

राष्ट्रीय अंडर 16 विजय मर्चेट ट्रॉफी (मल्टी डेज) हेतु राजस्थान अंडर 16 टीम घोषित

जयपुर 2 दिसंबर। आगामी 6 दिसंबर से खेले जाने वाली राष्ट्रिय अंडर 16 विजय मर्चेट ट्रॉफी (मल्टी डेज) में भाग लेने वाली राजस्थान अंडर 16 टीम का चयन राजस्थान जूनियर चयन समिति ने किया। राजस्थान का पहला मैच दिनांक 6 दिसंबर से 2024 को विजयवाड़ा में खेला जायेगा। राजस्थान अंडर 16 विजय मर्चेट ट्रॉफी टीम :- रजत बथेल (कप्तान), आदित्य वाघवा (उपकप्तान), राहुल, यथार्थ भारद्वाज, शिफान खान, शुभांग सिंह भाटी, अलोक गुर्जर, शरद सुथार, आराध्य अग्रवाल, गुरामन सिंह, पुरु देवद्वाल, सुजल परमार, अक्षय वैष्णव, मिमान खान, हर्ष सिंह, हितार्थ सोलंकी, तरुण कुमार, यश चौधरी, कुणाल राजपुरोहित, योजित चौधरी, आशीष, टीम दिनांक 3 दिसंबर को विजयवाड़ा के लिए प्रस्थान करेगी। राज्य स्तरीय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता (कोटा चैम्पियन) कोटा ने उदयपुर को पहली पारी को बदल के आधार पर हराया। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 14 क्रिकेट प्रतियोगिता के आज कोटा - उदयपुर टीमों के मध्य खेले जा रहे 2 दिवसीय फाइनल मैच के अंतिम दिन कोटा ने उदयपुर को पहली पारी की बदल के आधार पर हराकर प्रतियोगिता की चैंपियन बनी। प्रतियोगिता के समापन की प्रेजेंटेशन सेरेमनीमें आरसीए एडहॉक कमेट्टी सदस्य धर्मवीर सिंह शेखावतने प्रतियोगिता की विजेता , उपविजेताओं को ट्रॉफी व सभी खिलाड़ियों , मैच ऑफिशियल को मोमेंटो प्रदान किये।



ऑस्ट्रेलिया टीम दो गुटों में बंटी?

एडिलेड, 2 दिसम्बर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेले जा रही है। सीरीज का पहला टेस्ट पर्यटन में खेला गया था जिसे भारत ने जीत लिया। वहीं अब दोनों टीमों के बीच 6 दिसंबर से एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम में फूट की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि, ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम बैटर्स और बॉलर्स के ग्रुप में बंट गया है और टीम में मतभेद चल रहे हैं। कुछ पूर्व क्रिकेटर्स ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी है। हालांकि, अब ट्रेविस हेड ने इस पर बयान दिया है। ट्रेविस हेड ने कहा कि, ऑस्ट्रेलियाई टीम में किसी तरह का मतभेद नहीं है। हेड ने पर्यटन टेस्ट से पहले ट्रेविस हेड ने खुलकर अपनी बात रखी और कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में किसी तरह का मतभेद नहीं है। हेड ने पर्यटन टेस्ट को याद करते हुए कहा कि, मुझे याद है कि वह मैच जल्दी खत्म हो गया था। हमने उस मैच का भरपूर आनंद लिया था। फिर से ऐसा करना अच्छा होगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले



मैच में ऐसा होगा। हेड ने इसके साथ ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया की आउट ऑफ फॉर्म बेंचिंग और बॉलिंग यूनिट के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है। हेड ने कहा कि, हम दोनों डिपार्टमेंट यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से काफी उम्मीदे हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल गेम है। बल्लेबाजी में हम मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं।

एसएफए चैंपियनशिप 2024



स्वदेश खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता

जयपुर, 2 दिसंबर। एसएफए चैंपियनशिप 2024 जयपुर के चौथे दिन स्वदेश खिलाड़ियों ने एक्शन में मुख्य भूमिका निभाई। इसमें नीरज मोदी स्कूल, मानसरोवर की गोविल अजमेर ने स्वर्ण पदक जीता और महाराजा सवाई मान सिंह विद्यालय, रामबन्धल की लक्ष्म्या राजवत ने लड़कियों के अंडर-9 एकल वर्ग में दबदबा बनाया। खास बात यह रही की चैंपियनशिप का आधिकारिक रूप से सोमवार को शुभारंभ हुआ, जिससे आगे रोमांचक प्रतियोगिताओं के लिए मंच तैयार हो गया। दूसरी ओर, सेंट एक्सलम स्कूल, मानसरोवर के कविश चौधरी ने लड़कों की अंडर-10 टेनिस स्पर्धा के फाइनल में सिरसी रोड स्थित तेजोतर अनबाउंडेड के साहिल खान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। शहर में चैंपियनशिप के चौथे दिन सोमवार को एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, खो-खो और अन्य टूर्नामेंट भी शुरू हुए, जिसमें आने वाले दिनों में पदक स्पर्धाएँ निर्धारित हैं। इसके अलावा, लड़कों की अंडर-9 शतरंज स्पर्धा में, कैम्ब्रिज कोर्टवर्ल्ड स्कूल ने शंका मेहता और शौर्य शर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत स्वर्ण और रजत पदक जीता, जो क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे।

शाम के समय गुलाबी गेंद से खेलना चुनौतीपूर्ण होता है : पुजारा

एडिलेड, 2 दिसंबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले दूसरे दिन रात्रि टेस्ट मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि लाल और गुलाबी गेंद में अंतर होता है और शाम के समय गुलाबी गेंद से खेलना चुनौतीपूर्ण होता है। पुजारा ने कहा, जिसने भी गुलाबी गेंद से टेस्ट खेला है वह आपको बताएगा कि शाम के समय बल्लेबाजी करना सबसे मुश्किल होता है। उस समय रोशनी पूरी तरह से नहीं होती है, ना ही पूरा अंधेरा होता है उस समय स्ट्रेटिजिकली लाइट जलाई जाती है और तब आपको थोड़ा कम दिखता है। उस समय बल्लेबाजों के लिए गुलाबी गेंद खेलना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। उन्होंने, आपने देखा होगा कि लाल गेंद अधिक चमकती नहीं होती है। इसमें पेंट की कुछ अधिक लेयर होती है, जो जल्दी से नहीं जाती है। जब आप लाल गेंद का सामना कर रहे हो तो यह आम लेडर गेंद है जो जल्दी से पुरानी हो जाती है।



जबकि गुलाबी गेंद में अधिक समय तक चमक बनी रहती है। उन्होंने कहा, गुलाबी गेंद पर पेंट की अधिक लेयर होती है और जब यह पिच पर पड़ती है, सोम पर गिरती है या चमकीले हिस्से पर भी गिरती है तो इसमें थोड़ा अधिक जोरिखिम होता है। ऐसे समय में बल्लेबाज के तौर पर आपके पास कम समय होता है। आपके पास लाल गेंद खेलने जितना समय नहीं होता है और यही बड़ा अंतर है जिसमें बलना होगा।

भुवनेश्वर ने जीता पहला मुकाबला

अखिल भारतीय एस.बी.आई. इंटर सर्किल बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरु



पटना पर की 2-0 से एकतरफा जीत दर्ज

जयपुर, 2 दिसम्बर। भुवनेश्वर ने सोमवार से शुरु हुई अखिल भारतीय एस.बी.आई. इंटर सर्किल बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच जीत लिया। भुवनेश्वर ने पटना पर 2-0 से एकतरफा जीत दर्ज की। पहले एकल मुकाबले में भुवनेश्वर के अभिलाशा पाण्डा ने पटना के के.चर्जी को 21-17, 21-14 से हराया। युगल में जी.प्रसाद और सत्या को जोड़ी ने गौतम वर्मा और मोरीय को जोड़ी को 21-7, 21-11 से शिकस्त दी। प्रतियोगिता में पटना के 175 खिलाड़ी शामिल हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन उप-उप-अध्यक्ष एवं कॉर्पोरेट विकास अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने किया। इस मौके पर

सर्किल वेल्फेयर कमेट्टी के सचिव के विनोद तंवर, सी.एम.जी. (एचआर) राजीव कुमार, एसबीआई ओ.ए. के अध्यक्ष रामावतार सिंह जाखड़ और एस.बी.आई. ओ.ए. के महासचिव विनय कुमार, एस.ई.डब्ल्यू.ए. के अध्यक्ष अशोक कुमार मीणा, एस.आई.एस.बी.आई. एस.पी. के महासचिव एल. चन्द्र शेखर, ए.आई.एस.बी.आई. के वर्किंग प्रेसिडेंट पंकज कोशिक व एस.बी.आई. एस.एफ. के प्रेसिडेंट आर श्रीराम, टूर्नामेंट के चीफ रेफरी जगदीश खत्री और डिप्टी रेफरी विकास माधुर भी मौजूद थे। इससे पूर्व विनोद कुमार मिश्रा और राजीव कुमार ने बैडमिंटन खेलकर मैचों की विधिवत शुरुआत करवाई। उद्घाटन समारोह में मिश्रा ने कहा कि बैक शीर्ष ही खिलाड़ियों की भर्ती करेगा, उन्होंने कहा कि बैक संदेव खिलाड़ियों का संदेव सम्मान करता है और खेल एवं खिलाड़ियों को संदेव प्रोत्साहित करता है।

अंडर-19 एशियाकप: पाकिस्तान ने यूईई को 69 रनों से हराया

दुबई, 2 दिसंबर। शाहजेब खान (132) और मुहम्मद रियाजुल्लाह (106) रनों की बेहतरीन शतकीय पारियों के बाद अब्दुल सुभान (छह विकेट) की दमदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान ने सोमवार को अंडर-19 एशियाकप के ग्रुप ए के सातवें मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूईई) को 69 रनों से हरा दिया है। 315 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूईई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 57 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिये थे। याथिन राय (18), आर्यन सक्सेना (24) और अक्षत राय (पांच) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद एथन डिस्सा, मुहम्मद रयान ने पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी हुई। मुहम्मद रयान ने 66 गेंदों में एक चौके और तीन छक्के लगाते हुए (50) रन बनाये। नूरुल्लाह अयोबी (एक), अयान अफजल खान (15), अब्दुल्ला तारिक (एक) रन बनाकर आउट हुये।एथन डिस्सा ने 102 गेंदों में 11 चौके लगाते हुए (84) रनों की पारी खेली। यूईई की टीम निर्धारित 50 ओवरों में आठ विकेट पर 245 रन ही बना सकी और 59 रनों से मुकाबला हार।

महिला वर्ग में सम्भव डायग्नोस्टिक विजेता और शुभम केअर हॉस्पिटल उपविजेता

जयपुर, 2 दिसम्बर। डॉक्टर्स बैडमिंटन लीग का छठा संस्करण 22 नवंबर से स्पॉटिफ अकादमी में चल रहा था जो कि 1 दिसंबर को सम्पन्न हुआ। मुख्य अतिथि डॉ राजवंद चौधरी आज फाइनल मुकाबलों को देखने के लिए उपस्थित थे। मुकाबलों की समाप्ति के बाद उन्होंने विभिन्न वर्गों के विजेता, उपविजेता तथा तृतीय स्थान पर रहे खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया और उनका हौसला बढ़ाया। लीग संयोजक डॉ हरीश भारद्वाज ने बताया कि 1/12/2024 को सभी वर्गों के फाइनल मैच हुए। बांयज वर्ग में फाइनल में केडिया होटशॉर्ट्स ने शॉल्डर एंड नी सर्जरी क्लीनिक को हराया और विजेता बनी। तृतीय स्थान पर लिपि लेजेज्स और ऑट टाइटन्स रहे।

भारत ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 को दी मात

कैनबरा, 2 दिसम्बर। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 को कैनबरा के मनुका ओवर में 2 दिवसीय अभ्यास मैच में 6 विकेट से मात दी। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वह मिडिल ऑर्डर में खेले। वहीं शुभमन गिल ने अपना फिफ्टी जड़ा। वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि, इस दौरान विराट कोहली और ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी नहीं की। जसप्रीत बुभराव और रविचंद्रन अश्विन ने गेंदबाजी नहीं की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सैम कोनस्टास ने शतक जड़कर प्रभावित किया। पहला दिन शनिवार को बारिश के कारण बाधित रहा। टॉस तक नहीं हो सका। दूसरे और अंतिम दिन रविवार को भारत ने टॉस



जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। 50-50 ओवर का मैच बारिश के कारण 46-46 ओवर का हुआ। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 ने 43.2 ओवर में 240 रन बनाए। सैम कोनस्टास ने 97 गेंद पर 107 रन बनाए। हेन्रो जैकब्स ने 59 गेंद पर 61 रन ठोके। जैक क्लेटन ने 40 रन की पारी खेली। तो भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 4, आकाशदीप ने 2, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन

सुंदर और जडेजा ने 1-1 विकेट की सफलता हासिल की। वहीं भारत की पारी की बात करें तो, टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 256 रन बनाए। 17 रन की बहुत हासिल की। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल 27 और शुभमन गिल 50 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए। रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला। उन्होंने 3 रन बनाए। नितीश रेड्डी 42 और रविंद्र जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज खान 1 रन बनाकर आउट हुए। वाशिंगटन सुंदर 43 और देवदत्त पंडिकरत्न 3 रन बनाकर नाबाद रहे। चार्ली एंडरसन ने 2, लॉयड पोप, मैट नेशॉर और जैक क्लेटन को 1-1 विकेट मिला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 6 दिसंबर से दूसरा टेस्ट डे नाइट होगा।

फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर्स ट्रॉफी 2024

टीम इंडिया-सीनियर व इंडिया-बी में फाइनल

जयपुर, 2 दिसंबर। फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर्स ट्रॉफी 2024 का तीसरा दिन काफी रोमांच से भरा हुआ था। टीम इंडिया-ए के फाइनल में प्रवेश करने पर मैदान और दर्शकों में काफी उत्साह और जुनून देखने को मिला। यह ट्रॉफी राजस्थान डिसेबल्ड क्रिकेट एसोसिएशन (एसोसिएशन) द्वारा पैट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित क्रिकेट एकेडमी में आयोजित की जा रही है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे खेला जाएगा। फिजिकली डिसेबल्ड चैलेंजर्स ट्रॉफी 2024 के तीसरे दिन का पहला नॉक आउट मैच इंडिया-ए और इंडिया-सी के बीच खेला गया। पहले खेलते हुए इंडिया-ए ने एक विशाल स्कोर 173/7 खड़ा किया। टीम इंडिया-ए ने शुरुआती तीन विकेट्स बहुत ही कम स्कोर (20/3) पर खोये, जिसके बाद



टीम के कप्तान रविंद्र शांते ने 36 गेंदों का सामना करते हुए 56 रन और दीपेश भारती ने 27 गेंदों में 46 रन की एक महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। टीम इंडिया-सी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपना पहला विकेट दूसरे ही ओवर में खो दिया। जसवंत सिंह ने टीम के लिए एक संघर्षपूर्ण पारी का प्रदर्शन करते हुए 34 गेंदों में 29 रन की नाबाद पारी खेली। टीम इंडिया-ए ने 46 रन से यह मैच जीता। इंडिया-ए के कप्तान रविंद्र शांते को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।

निशानेबाज तनुज राज सिंह ने राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता



जयपुर, 2 दिसंबर। स्पोर्ट्स फार आल चैंपियनशिप जयपुर 2024-25 सत्र-02 में राजस्थान राज्य के 17 वर्षीय युवा निशानेबाज तनुज राज सिंह ने रास सिंह ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए पीप साइट राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका प्रदर्शन ने केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को उजागर करता है बल्कि राजस्थान को सम्मान भी दिलाता है और राज्य भर के आगामी निशानेबाजों को प्रेरित करता है। उनकी सफलता वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण के दर्शाती है, जो उन्हें क्षेत्र में महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए एक आदर्श बनाती है। युवा निशानेबाज तनुज राज सिंह ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया है, जिससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर शूटिंग खेलों में राजस्थान की बढ़ती प्रतिष्ठा में योगदान मिला है। राजस्थान राइफल एसोसिएशन, राज्य सरकार, खेल संघ ने जहां प्रशंसक तनुज राज सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। उनकी उपलब्धियाँ राजस्थान के एथलीटों की कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

// राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ // जयपुर दोनों वर्गों में चैंपियन



जयपुर, 2 दिसंबर। चित्तौड़गढ़ में सोमवार को संपन्न चार दिवसीय 41वीं बालक राजस्थान राज्य जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता (बालक व बालिका)-2024-25 में जयपुर ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए बालक एवं बालिका वर्ग के खिताब अपने नाम किये। बालक के खिताबी मुकाबले में जयपुर ने जहां आएएसएससी अकादमी-जैसलमेर को 26-24 से हराया। मध्यंतर तक दोनों टीमों 12-12 से बराबरी पर थीं। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में जयपुर ने दुलमाना हैंडबॉल अकादमी-हरामणागढ़ को 21-11 से हराया। मध्यंतर तक विजेता टीम 11-05 से आगे थी। इससे पहले तीसरे स्थान के लिये खेले मैचों में दोनों वर्गों में श्रीगंगानगर ने जीत दर्ज की। बालक वर्ग में श्रीगंगानगर ने

चित्तौड़गढ़ को 28-18 (10-06) से तथा बालिका वर्ग में श्रीगंगानगर ने सीकर को 15-13 (07-07) से हराया। राजस्थान राज्य हैंडबॉल संघ के मानद सचिव यश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के बालक एवं के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आएएसएससी अकादमी-जैसलमेर के आशीष को स्व. लोकेश सिंह गौड़ तथा बालिका वर्ग की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जयपुर की टीना को स्व. तनेगम मेघवाल की स्मृति पर थी। वहीं बालिका वर्ग के फाइनल में जयपुर ने दुलमाना हैंडबॉल अकादमी-हरामणागढ़ को 21-11 से हराया। मध्यंतर तक विजेता टीम 11-05 से आगे थी। इससे पहले तीसरे स्थान के लिये खेले मैचों में दोनों वर्गों में श्रीगंगानगर ने जीत दर्ज की। बालक वर्ग में श्रीगंगानगर ने



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की। राज्यपाल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह शिफ्टाचार भेंट थी।

‘पहले साल में 47 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलाम कर देश में पहला स्थान’

मुख्यमंत्री ने खान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लक्ष्य बनाकर काम करने को कहा

जयपुर, 2 दिसंबर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं तथा लगभग 30 लाख लोगों को खनन से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि खनिज सम्पदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र में राज्य में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग खनन खोज कार्य में तेजी लाते हुए, नये खनन क्षेत्रों की पहचान करे तथा नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए। शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा, यह बेहद हर्ष का विषय है कि वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही 47 प्रधान

मुख्यमंत्री ने कहा, पिछली सरकार ने 5 साल में 34 प्रधान खनिज ब्लॉक नीलाम किये थे, यह सरकार एक वर्ष में 47 ब्लॉक नीलाम कर चुकी है। इसी प्रकार पिछली सरकार ने अप्रधान, खनिज के 5 साल में 286 प्लॉट नीलाम किये, जबकि, यह सरकार एक वर्ष में 426 प्लॉट्स नीलाम कर चुकी है।

समीक्षा बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान व पेट्रोलियम टी. रविकांत ने प्रस्तुतिकरण देकर विभाग के कार्यक्रमों, नवाचारों व योजनाओं की जानकारी दी।

खनिज ब्लॉक नीलाम कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि एक सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में केवल 34 ब्लॉक ही नीलाम किये थे। उन्होंने कहा कि इसी तरह, वर्तमान सरकार ने प्रथम वर्ष में अप्रधान खनिज के कार्यकाल में मात्र 282 प्लॉट्स ही नीलाम की है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में मात्र 282 प्लॉट्स ही नीलाम हुए थे। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार खनन से राज्य के राजस्व को

बढ़ाने एवं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। शर्मा ने कहा कि हाल ही में कैबिनेट ने नई खनिज नीति 2024 तथा नई एम-सैण्ड नीति 2024 को मंजूर दी है। नई खनन नीति से प्रदेश में खनन आधारित उद्योगों, औद्योगिक निवेश, युवाओं व स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं राजस्व में बढ़ोतरी होगी। साथ ही, अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी यह नीति महत्वपूर्ण

साबित होगी। उन्होंने कहा कि नई एम-सैण्ड नीति से प्रदेश में एम-सैण्ड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम-सैण्ड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

बैठक में खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रगति, डी.एम.एफ.टी. मद से प्राप्त राशि के सही उपयोग की गाइडलाइन, विभागीय भर्तियां, सिरीमिक एवं रेयर मेटल के सेक्टर ऑफ एक्सप्लोरेशन की प्रगति, भारत सरकार के स्तर पर लॉन्ग मुदे सहित, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम टी. रविकांत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से खान विभाग के कार्यक्रमों, नवाचारों एवं योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव सुधाश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय आलोक गुप्ता सहित, विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

33 प्रतिशत महिला आरक्षण पर बार काउन्सिल को पक्षकार बनाया

जयपुर, 2 दिसंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर, द बार एसोसिएशन जयपुर सहित प्रदेश की बार एसोसिएशन चुनाव में महिला अधिवक्ताओं को 33 फीसदी आरक्षण नहीं देने के मामले में बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने को कहा है।

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता हेमा तिवाड़ी की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट बार और द बार एसोसिएशन को नोटिस तामील होने के बाद भी, उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ है। ऐसे में लगता है कि उन्हें महिला आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है।

सुनवाई के दौरान, बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान की ओर से अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं। बार

राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में यह आदेश दिये।

काउन्सिल ऑफ राजस्थान (बी.सी.आर.) की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता स्वयं बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान का चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में व्यक्तिगत हितों को लेकर जनहित याचिका पेश नहीं हो सकती। वहीं, महिला आरक्षण को लेकर नियम बनाने का अधिकार बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को है और याचिका में बार काउन्सिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस पर कोर्ट ने बी.सी.आई. को पक्षकार बनाने के आदेश देते हुए मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को रखी है।

जनहित याचिका में कहा गया कि नारी शक्ति वंदन अधियान-2023 के तहत, महिला आरक्षण अधिनियम लाया गया, जिसके तहत महिलाओं को

संसद में 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2024 को अदिति चौधरी बनाम बार काउन्सिल ऑफ दिल्ली व अन्य के मामले में बार काउन्सिल ऑफ दिल्ली को निर्देश दिया है कि वह बार काउन्सिल के चुनावों में महिला अधिवक्ताओं के लिए भी 33 फीसदी सीट आरक्षित रखे। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने भी बी.सी.आर. को महिला अधिवक्ताओं को 33 फीसदी आरक्षण देने के लिए 28 अगस्त को प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उसके प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों के पद पर महिला नियुक्त हो चुकी हैं, लेकिन बी.सी.आर. में चैयमैन व वाइस चैयमैन के पद पर कभी भी कोई महिला नियुक्त नहीं हुई। इसलिए बी.सी.आर., हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर सहित अन्य जिला बार एसोसिएशनों में भी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाए।

‘केन्द्र सरकार बंगलादेश में संयुक्त राष्ट्र सेना तैनात कराये’

कोलकाता, 02 दिसंबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को बंगलादेश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चिंता व्यक्त की और संकटग्रस्त देश में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को तैनाती के लिए केंद्र सरकार से पहल करने का आग्रह किया।

बनर्जी ने विधानसभा में कहा, हम बंगलादेश के मामलों पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा रुख स्पष्ट है कि बंगलादेश पर केंद्र जो भी फैसला करेगा, हम सरकार के साथ ही हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई आना चाहे और साथ में खाना

ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा, केन्द्र बंगलादेश पर जो भी फैसला करेगा, हम उसका साथ देंगे।

खाए, तो हम उसे समायोजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्थिति की मांग हो, तो राज्य विधानसभा सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन की तैनाती के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बंगलादेश में सतार गए भारतीयों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया।

बनर्जी ने विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से संसद सत्र के दौरान बंगलादेश की स्थिति के बारे में भारत के रुख पर बयान देने की भी मांग की।

मोदी सरकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) खिलाफ हंगामा कर रहा था क्योंकि असम विपक्ष को उसके स्थान प्रस्तावों की अनुमति नहीं दे रहे थे। जयवाम रमेश ने यह संकेत दे दिया है कि दोनों पीठासीन अधिकारी सरकार के दबाव में किसी स्थान प्रस्ताव को अनुमति नहीं दे रहे थे।

पहली बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) हिन्दुओं पर हो रहे हमले का विरोध किया। उन्हें भय है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हिंसा जारी रही तो भारत में उसकी गंभीर प्रतिक्रिया हो सकती है।

हिंदुओं पर हमले से बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के समक्ष भारी अनिश्चिता है। वे खुद को अलग-थलग महसूस कर रहे हैं। बांग्लादेश की आजादी से पहले, पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना ही हिंदुओं को निशाना बनाती थीं।

आजादी के बाद, हिंदुओं पर हमले कम होने की बजाय बढ़ गए। बदले माहौल में, जब बंगाली सत्ता में आए, तब उन्होंने ही हिन्दुओं के खिलाफ साम्प्रदायिक हिंसा की। यह स्पष्ट है कि बांग्लादेश में बांग्ला पहचान, मुस्लिम पहचान में कहीं खो गई है और कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इन कट्टरपंथियों को काफी हद तक नियंत्रण में रखा था। पर अब शेख हसीना नहीं हैं तथा सब कुछ कट्टरपंथियों के हाथ में है। अंतरिम सरकार कट्टरपंथियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। देश में ये ताकतें लगातार हिंसा कर रही हैं और इससे भारत में भी नई ताकतें उभर रही हैं, खासकर पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र में।

अडानी की मुश्किलें ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चलना कठिन हो रहा है। प्रवक्ता ने कहा, “हम बांग्लादेश पावर डिपॉजिटमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही, सरकारी अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद बनाये हुये हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी बकाया राशि का मुद्दा जल्दी निबट जायेगा।”

रिपोर्टों के अनुसार, अडानी पावर की बांग्लादेश की तरफ बकाया राशि 650 मिलियन डॉलर से बढ़कर 900 मिलियन डॉलर हो गई है। पिछले दो महीनों में, बांग्लादेश ने 182 मिलियन डॉलर का भुगतान कर दिया है।

रिपोर्ट कहती हैं कि बांग्लादेश चाहता है कि अडानी पावर कीमतों में काफी कमी करो लेकिन अडानी पावर के प्रवक्ता का कहना है कि उनके पास ऐसा कोई संकेत नहीं है कि बांग्लादेश अपने बिजली-खरीद-समझौते पर पुनर्विचार कर रहा है।

रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश की बिजली सप्लाई करने वाले सप्लायरों की तुलना में, अडानी पावर की दरें सबसे अधिक हैं। कम्पनी की प्रति यूनिट लागत 14.87 टका है, जबकि अन्य भारतीय सप्लायरों के लिये यह लागत औसतन 9.57 टका प्रति यूनिट है।

अनूप बरतरिया का गिरफ्तारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बदलने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने पूर्व में जारी गिरफ्तारी वारंट की तामील स्पेशल मैसैन्जर से कानून को कहा है। अदालत ने यह आदेश अनूप बरतरिया व अन्य की ओर से दायर प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ 23 मई, 2024 को प्रसंज्ञान लेकर समान जारी किए थे। वहीं, 2 फरवरी, 2018 को इनके जमानती वारंट जारी किए गए।

आरोपियों को अदालती आदेश की जानकारी होने के बावजूद, वे अदालत में पेश नहीं हुए। ऐसे में उन्हें विधि सम्मत तरीके से गिरफ्तारी वारंट के जरिए तलब किया है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि उनका परिवार से राजीमाना हो गया है और विवादित चेक राशि भी जमा कराई जा चुकी है।

एन.आई. एक्ट की धारा 138 जमानती अपराध है। उन पर जमानती वारंट की तालीम नहीं हुई है और सीधे

गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किए जा सकते। ऐसे में गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदला जाए, जिसका विरोध करते हुए परिवारदी यूको बैंक की ओर से अधिवक्ता दिनेश गंग ने कहा कि आरोपियों को प्रकरण की पूरी जानकारी होने के बावजूद, वे अदालत में हजरत नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनके प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट को जमानती वारंट में बदलने से इनकार कर दिया है।

सरकारी कर्मचारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अदालत राज्य सरकार के दिन-प्रतिदिन के तबादला आदेश में दखल देगी तो जनहित में होने वाले काम अटक जाएंगे। इसके साथ ही, अदालत ने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान के अर्स्टेंट प्रोफेसर्स की ओर से तबादला आदेश के खिलाफ पेश याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को नए पदों पर कार्यभार ग्रहण करने को कहा गया है। अदालत ने कहा कि यदि वे इन पदों पर कार्यग्रहण ग्रहण नहीं करते हैं तो कृषि विवि उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राजेंद्र सिंह व अन्य की याचिकाओं पर दिए। अदालत ने कहा कि स्वायत्तशासी संस्था होने के चलते कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों की परिभाषा में नहीं आते हैं। राज्य सरकार इनके वित्त मामलों में ही सीमित भूमिका रखती है। ऐसे में राज्य सरकार के तबादला संबंधी आदेश उन पर लागू नहीं होते हैं।

याचिका में कहा गया कि

याचिकाकर्ता कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा में कोट विज्ञान के सहायक प्रोफेसर पद पर अक्टूबर, 2020 से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 4 जनवरी, 2023 को अधिसूचना जारी कर सभी विभागों, निगमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों का तबादला करने पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद, याचिकाकर्ताओं का यह से तबादला कर दिया। इसके अलावा, नियमानुसार पांच साल के कार्यकाल से पहले उनका तबादला नहीं किया जा सकता। इसका विरोध करते हुए, कृषि विवि के अधिवक्ता हिमांशु ठोसिया ने बताया कि विवि स्वायत्तशासी संस्था है और राज्य सरकार हाल ही में पत्र जारी कर स्पष्ट कर चुकी है कि तबादलों पर रोक का आदेश विवि पर लागू नहीं होता। इसके अलावा, याचिकाकर्ता विवि में विभिन्न पदों पर करीब तीन दशकों से काम कर रहे हैं। ऐसे में कुलपति को उनका तबादला करने का पूरा अधिकार है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

अकाल तख्त ने प्रकाश सिंह बादल को दोषी माना, खिताब रद्द

चंडीगढ़, 02 दिसंबर। सर्वोच्च सिख धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक रहे दिवंगत प्रकाश सिंह बादल का ‘फ़ख्र-ए-कौम पथ रत्न’ खिताब रद्द करने की घोषणा की। संस्था का कहना था कि बादल सिरसा डेरा प्रमुख गुरुमति सिंह राम रहौम को माफी देने के प्रकरण में भी संलिप्त रहे थे। अकाल तख्त जल्येदार ज्ञानी रघवीर सिंह और अन्य ने इसी के साथ शिरोमणि अकाली दल की कोर्ट कमेटी को पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस्तीफे को स्वीकार करने का निर्देश दिया। अकाल तख्त सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर चुका था और सोमवार को अकाली नेताओं को सजा सुनाई जा रही थी। अकाल तख्त ने अकाली नेताओं की दरबार साहब परिसर में बाथरूम सफाई, बर्तन साफ करने और श्रद्धालुओं के जुते साफ करने व गुरद्वारे में कीर्तन में मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

‘हर मतदान केन्द्र पर वोटर्स की संख्या कैसे बढ़ी?’

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि हर बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से बढ़कर 1500 कैसे हो गई

वीफ जस्टिस संजीव खन्ना एवं जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने चुनाव आयोग को इस पर एक लघु शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में मांग की गई है कि 1957 से 2016 तक सभी पोलिंग बूथ पर 1200 वोटर्स की संख्या का नियम पालन हो रहा था पर एकाएक यह संख्या बढ़ा दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2025 की तारीख दी है।

तारीख मुकर्र कर दी। इससे पहले 27 अक्टूबर को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया था कि मतदाताओं की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने से वंचित समूह

चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति को वोट डालने में अधिक समय लगेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मतदान केंद्र पर लंबी कतारों और लंबी प्रतीक्षा अवधि मतदाताओं को वोट डालने से रोकेंगी। उन्होंने दावा किया

किसानों ने दिल्ली मार्च एक सप्ताह स्थगित किया

केन्द्र सरकार को सात दिन में मांगें मानने का अल्टीमेटम

नोएडा, 02 दिसंबर। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर सोमवार को दिनभर पुलिस प्रशासन की सांसों अटकी रहीं। किसान दादरी-नोएडा लिंक रोड पर महाभारत फाईअंशिवर पर एकत्र हुए और सुबह करीब 11.30 बजे अपना मार्च शुरू किया। पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेड लगाए और भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनाती की गई। इसके कारण दिल्ली-नोएडा सीमा पर भारी जाम लग गया।

हालांकि किसानों ने एक हफ्ते के लिए अपना आंदोलन टाल दिया है, लेकिन इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही रुकेंगे। यह फैसला किसान नेताओं की ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया। इसके बाद नोएडा एक्सप्रेस-वे से

किसानों द्वारा दिल्ली मार्च स्थगित करने व दलित प्रेरणा स्थल पर रुकने की घोषणा के बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से जाम समाप्त हुआ।

बैरिकेडिंग हटा दी गई और आवाजाही शुरू हो गई है।

किसानों ने अपनी मांगों पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है। इस दौरान किसान दलित प्रेरणा स्थल पर आंदोलन करेंगे। अगर एक हफ्ते में मांगें नहीं मानी गईं, तो किसान फिर से दिल्ली कूच करेंगे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर यातायात

‘पूर्व सी.जे.आई... आज होगी...’

(प्रथम पृष्ठ का शेष) ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूजा स्थल अधिनियम-1991 के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। यही हमारी स्थिति है। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। मगर इसके लिए सबसे जरूरी है कि संसद को काम करने दिया जाना चाहिए।

आज होगी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) मुख्यमंत्री के रूप में ढाई साल का कार्यकाल और दिया जाये। उन्होंने कहा कि सिन्डे ने प्रधानमंत्री तथा भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं को आश्चर्य कर दिया है कि भाजपा नये मुख्यमंत्री के रूप में जिसका भी चयन करती है, शिव सेना उसका समर्थन करेगी।

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने ढील देने से इंकार किया

नयी दिल्ली, 02 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार करते हुए, सोमवार को कहा कि संबंधित आंकड़ों की समीक्षा के बाद ही वह पांच दिसंबर को कोई छूट देने पर विचार करेगा।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सी.ए.क्यू.एम.) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती की ढील देने की गुहार अस्वीकार करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए ग्रेडेड एक्शन रिसपास प्लान (ज.आ.ए.पी.) स्टेज-4 के तहत, तीसम अतिरिक्त फिलहाल लागू रहेंगे।

पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को भी संभल जाने से रोका

कांग्रेस नेताओं ने कहा, उन्हें रोककर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है

लखनऊ, 02 दिसंबर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने सोमवार को संभल जाने का प्रयास किया, मगर पुलिस ने जिला प्रशासन द्वारा दस दिसंबर तक लगायी गयी रोक का हवाला देते हुये उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी।

गौरतलब है कि अदालत के आदेश पर जाना मसिबद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के सर्वे के दौरान पिछले दिनों संभल में षडकी हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गयी थी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वह मृतक के

परिजनों को ढाढस बंधाने के लिये जा रहे थे, मगर तात्कालिक सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन्हें जाने की अनुमति नहीं देकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि एक तरफ सरकार अपने दिल्ली को निर्वहन करने में असफल रही और दूसरी तरफ तानाशाही रवैया अपनाते हुए कांग्रेस नेताओं को मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदन व्यक्त करने जाने से रोकने के लिए एह-अलोकतांत्रिक हथकंडा अपना रही है। उन्होंने कहा कि

कांग्रेस का सवैधानिक अधिकार है कि वह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं और मुद्दों को सुने और सदन में उठाये। मगर योगी सरकार को इस बात का भय है कि कांग्रेस नेताओं के संभल जाने से सच बाहर आ जायेगा और वह बेनकाब हो जायेगा। राय ने कहा कि 24 नवंबर की घटना के बाद कांग्रेस ने यह एलान किया था कि हम पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आगामी दो दिसंबर को संभल जायेंगे, क्योंकि सरकार द्वारा 30 नवंबर तक विपक्षी नेताओं के संभल जाने पर रोक लगा दी गयी है।